दिल्ली, एन.सी.आर. व सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक लोकप्रिय मासिक

उद्योग विहार

निष्पक्ष मासिक समाचार पत्र

Regd.No.-UPHIN/2004/15489 www.udyogviharnp.com प्रधान सम्पादक : सत्येन्द्र सिंह

मैडम तुसाद में लगेगा अनुष्का शर्मा का बोलने वाला.... P-8

वर्ष : 14 ▸ अंक : 2 ▸ गाजियाबाद, जुलाई, 2018 ▸ मूल्य : 4 रूपया ▸ पृष्ठ : 08 E-mail : udyogviharnp@yahoo.com

पर्यावरण के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए सत्येन्द्र सिंह को 'सोशल इम्पैक्ट अवार्ड'

संस्था का मकसद पॉलीथिन के दुष्प्रभावों से लोगों को जागरूक करना तथा स्वच्छ एवं हरित भारत के निर्माण के लिए लोगों को सन्देश देना है ताकि हम अपने भारत को स्वच्छ, हरित एवं स्वस्थ बना सकें

गाजियाबाद। पर्यावरण के क्षेत्र में कार्य कर रहे उत्थान समिति के चेयरमैन सत्येन्द्र सिंह को उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए दिल्ली स्थित कॉस्टीटूशन क्लब में आयोजित भव्य समारोह में ''सोशल इम्पैक्ट अवार्ड'' से सम्मानित किया गया। उनको यह अवार्ड लोकसभा सांसद एवं अभिनेत्री किरण खेर ने दिया। इस अवसर पर देश विदेश की कई गणमान्य हस्तियों के अलावा भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्याम जाजू, लोकसभा सांसद एवं भोजपुरी अभिनेता मनोज तिवारी, फिल्म अभिनेत्री पूनम ढिल्लो इत्यादि तमाम लोग उपस्थित थे। इस अवसर पर राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्याम जाजू ने उत्थान समिति के द्वारा किये जा रहे उत्कृष्ट कार्यों की सराहना की तथा कहा कि हमारे प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी भी चाहते हैं कि इसी तरह सभी लोग यदि आगे बढ़कर देश की सेवा में योगदान देंगे तो एक दिन हम अपने सपनों के भारत का निर्माण अवश्य कर पायेंगे। अतः सभी को पर्यावरण को बचाने के लिए आगे आना होगा तथा लोगों को जागरूक करना होगा। सत्येन्द्र सिंह ने अवार्ड मिलने के बाद कहा कि अवार्डों से हमारी जिम्मेदारी और बढ़ जाती है तथा हमें अपने बच्चों के भविष्य को बचाने के लिए पर्यावरण को बचाना ही होगा अन्यथा हम अपने बच्चों को सिर्फ विशाक्त पर्यावरण के रूप में जहर देने का कार्य करेंगे। अतः अब भी यदि हम चेत गए तो हमारे बच्चों का भविष्य उज्जवल होगा। उन्होंने कहा कि उत्थान समिति द्वारा तमाम अच्छे कार्य किये जा रहे हैं जिसमें पर्यावरण की रक्षा के लिए लोगों को जागरूक करना प्रमुख है। उन्होंने कहा कि संस्था का मकसद पॉलीथिन के दुष्प्रभावों से लोगों को जागरूक करना तथा स्वच्छ एवं हरित भारत के निर्माण के लिए लोगों को सन्देश देना है ताकि हम अपने भारत को स्वच्छ, हरित एवं स्वस्थ बना सकें।

उद्योग विहार

निष्पक्ष गारिक रागाचार पत्र

श्रम–जगत

E-mail : udyogviharnp@yahoo.com

गाजियाबाद, जुलाई, 2018

विभिन्न प्रदेशों का न्यूनतम वेतन

U.P. Minimum Wages

General

w.e.f. 01/04/2018 To 30/09/2018

Category Of Workers	Minimum Wages
Un-Skilled	7613.42
Semi Skilled	8374.77
Skilled	9381.06

Engineering (50 to 500)

w.e.f. 01/02/2018 To 31/07/2018

Category Of Workers	Minimum Wages
Un-Skilled	8903.10
Semi Skilled	9776.65
Skilled	10853.64

Engineering (above 500)

Category Of Workers	Minimum Wages
Un-Skilled	9333.89
Semi Skilled	10267.28
Skilled	11200.67

Delhi Minimum Wages

w.e.f. 01/04/2018

Category Of Workers	Minimum Wages
Skilled	16858.00
Semi Skilled	15296.00
Un-Skilled	13896.00

Rajasthan Minimum Wages

w.e.f. 01/01/2018

Category Of Workers	Minimum Wages
Un-Skilled	5338.00
Semi Skilled	5798.00
Skilled	6058.00
Highly Skilled	7358.00

Gujrat Minimum Wages

w.e.f. 01/04/2018 To 30/09/2018

Category Of Workers	Minimum Wages
Zone-I	
UnSkilled	8117.20
Semi Skilled	8325.20
Skilled	8559.20
Zone-II	
UnSkilled	7909.20
Semi Skilled	8117.20
Skilled	8325.20

Punjab Minimum Wages

w.e.f. 01/03/2018

Category Of Workers	Minimum Wages
Highly Skilled	10561.17
Skilled	9529.17
Semi Skilled	8632.17
Un-Skilled	7852.17

Haryana Minimum Wages

w.e.f. 01/01/2017

Category Of Workers	Minimum Wages
Un-Skilled	8280.20
Semi Skilled-A	8694.20
Semi Skilled-B	9128.91
Skilled-A	9585.35
Skilled-B	10064.62
Highly Skilled	10567.85

बीएसएनएल ने शुरू की देश की पहली इंटरनेट टेलिफोन सेवा

नई दिल्ली। सरकारी टेलिकॉम कंपनी बीएसएनएल ने गुरुवार को देश की पहली इंटरनेट टेलिफोन सेवा पेश करने की घोषणा की। कंपनी की यह सेवा 25 जुलाई से शुरू हो रही है। इससे बीएसएनएल के यूजर्स को उसके ह्यविंग्सह्ल मोबाइल ऐप से देश भर में किसी भी टेलीफोन नंबर पर कॉल करने की सुविधा मिलेगी। इसके लिए सब्स्क्राइबर को 1,099 रुपये का वार्षिक शुल्क देना होगा। उसके बाद वह बीएसएनएल या किसी अन्य कंपनी के वाई-फाई से देशभर में असीमित कॉल कर सकेंगे।

अभी देश में मोबाइल ऐप पर कॉल करने की सुविधा किसी खास ऐप के जरिये ही मिल रही है। लेकिन अब इस ऐप से किसी भी फोन नंबर पर कॉल कर सकने की सुविधा होगी। इस सेवा का शुभारंभ करते हुए दूरसंचार मंत्री मनोज सिन्हा ने कहा, 'मौजूदा प्रतिस्पर्धी माहौल में बीएसएनएल का बाजार में हिस्सेदारी बढ़ाना एक सराहनीय कार्य है।

इंटरनेट टेलिफोन सेवा शुरू करने के लिए मैं बीएसएनएल के प्रबंधन को बधाई देता हूं। यह सेवा यूजर्स को बिना सिम के कॉल करने की सुविधा देगी।' कंपनी के चेयरमैन एवं एमडी अनुपम श्रीवास्तव ने कहा कि इसके लिए रजिस्ट्रेशन एक-दो दिन में शुरू हो जाएगा और यह सेवा 25 जुलाई से लागू होगी। उन्होंने कहा कि इस सुविधा से विदेश में 'विंग्स' का इस्तेमाल करने वाले लोग भारत में किसी भी नंबर पर कॉल कर सकेंगे। इस ऐप का दुनियाभर में कहीं भी इंटरनेट के माध्यम से उपयोग कर कॉल की जा सकती है।

इस ऐप को बीएसएनएल द्वारा जारी एक मोबाइल नंबर से जोड़ दिया जाएगा, लेकिन कंपनी के 'विंग्स' ऐप के यूजर के लिए उसे मोबाइल या लैंडलाइन का अलग से कनेक्शन नहीं लेना होगा। श्रीवास्तव ने कहा कि कंपनी के मौजूदा लैंडलाइन ग्राहकों को एक अलग फायदा होगा। वे अपनी जगह पर निर्भर किए बिना ऐप पर इनकमिंग कॉल प्राप्त कर सकेंगे।

शहरी, रूरल यूजर्स के लिए अलग ब्रैंड रखेंगी वोडा-आइडिया

नई दिल्ली। वोडाफोन इंडिया और आइडिया सेल्युलर के मर्जर के बाद दोनों कंपनियां अपने ब्रैंड्स को लेकर सतर्कता बरतेंगी। एक्सपर्ट्स का कहना है कि नई एंटिटी नया ब्रैंड बनाने में जल्दबाजी नहीं करेगी क्योंकि इससे कस्टमर्स भ्रमित हो सकते हैं। मर्जर को लेकर इन दोनों टेलिकॉम कंपनियों के साथ काम कर रहे एक एनालिस्ट ने कहा, 'दोनों कंपनियों के नाम को मिलाया जा सकता है।

LEGAL INFOSOLUTIONS PVT. LTD.

ISO 9001 : 2008

A COMPLETE H.R., LABOUR LAWS & PAY ROLL OUT SOURCING MANAGEMENT

When we are at your back please stopworrying about maintaining records of Factory Act, Shop & Commercial Establishments Act, Contract Labour and Abolition Act, ESIC Act, PF Act, (Boiler) IBR Act, and handling cases relating to Labour Commissioner Office. We feel ourselves much competent in solving such problems due to our sincere working and wide contacts.

We have a full-fledged office set-up having most modern communication facilities (LAN, e-mail, internet, fax, and integrated telecommunication system), fully computerized environment with highly qualified and competent staff to render efficient and prompt services to our esteemed clients.

Our company is the first ISO-9001:2008 CERTIFIED company in India in this category.

OUR SCOPE OF WORK -

We are committed to provide satisfactory services to the customers by delivering prompt & quality output at value prices. Our end-to-end service includes;

- Payroll
- TDS
- ESI Act
- EPF Act
- Minimum Wages Act
- Bonus Act
- Payment of Gratuity Act
- Standing Order
- Workmen Health & Safety Policy
- First Aid Training & Certificates
- Factory Plan & Site Plan
- Factory Act-1948
- Shop & Establishment Act

Our Website : www.legalipl.com, **CMD -** 9818036460 / 9818697406

H.O. : SH-295, 1st FLOOR, SHASTRI NAGAR, GHAZIABAD (U.P.) INDIA.
PH. : 0120-4122901, 4108794,
Mobile : 9910771102/04

B.O. : D-129, 1st Floor, Sector-10, NOIDA, GAUTHAMBUDH NAGAR, (U.P.) INDIA.
Ph. : 0120-4222307

E-mail : legalipl@yahoo.com, legaliplho@yahoo.com

उत्थान समिति ने दिल्ली में बच्चियों के साथ पौधे लगाये तथा बीज-बम के बारे में जागरूक किया

गाजियाबाद। उत्थान समिति के चेयरमैन सत्येन्द्र सिंह ने दिल्ली में कात्यायनी बालिका आश्रम में बच्चियों के साथ स्लैप की संस्थापक मृगांका डडवाल के साथ पौधे लगाये तथा

❑ मृगांका डडवाल ने आश्रम की बच्चियों को समझाया पौधा रोपण का महत्व

आश्रम की बच्चियों को पौधा रोपण के महत्व के बारे में समझाया। उनको बीज–बम के बारे में बताया की कैसे इस बीज–बम से हम पौधा रोपण कर सकते हैं। इस बीज–बम को बनाने के लिए नारियल की छाल, गोबर, और कुछ मिनरल का इस्तेमाल किया जाता है। नारियल की छाल का प्रयोग इसलिए लिया जाता है ताकि ये बीज–बम फूटे नहीं और अधिक पानी पड़ने पर खराब ना हो। इस बीज–बम के बीच में पौधे के बीज को डाला जाता है। इसमें नीम, तुलसी, चाइना बेरी, जामुन, इत्यादि बीज डाले जाते हैं। बच्चों से पर्यावरण के बारे में प्रश्न पूछे गए जिसका सभी ने अच्छे से जवाब दिया फिर उनको पर्यावरण के महत्व के विषय पर भी जानकारी दी गयी।

उद्योग विहार
निष्पक्ष गारिक रागाचार पत्र
E-mail : udyogviharnp@yahoo.com
Editorial
04 P.
गाजियाबाद, जुलाई, 2018

सम्पादकीय

चुनाव का समय

सत्येन्द्र सिंह

लोकसभा और विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराने की सलाह लंबे समय से दी जाती रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस विचार को गंभीरता से आगे बढ़ाने का प्रयास किया है। इस सिलसिले में नीति आयोग, विधि आयोग और इस मामले से जुड़ी संसद की स्थायी समिति ने भी विचार किया है। अभी विधि आयोग ने सरकार को अपनी सिफारिशें भेजने से पहले विभिन्न राजनीतिक दलों, क्षेत्रीय पार्टियों और प्रशासनिक अधिकारियों के साथ तीन दिवसीय चर्चा शुरू की। इसमें कुछ दलों ने देश भर में एक साथ चुनाव कराने पर सहमति जताई, जबकि ज्यादातर दलों ने इसे असंभव और अव्यावहारिक विचार बताया। जाहिर है, इस पर आम राय नहीं बनने से इस विचार को अमली जामा पहनाना संभव नहीं होगा। दरअसल, देश भर में एक साथ चुनाव कराने पर इसलिए बल दिया जा रहा है कि इससे चुनावों पर होने वाला खर्च कम होगा और निरंतर चलने वाली चुनाव प्रक्रिया से निर्वाचन आयोग, राजनीतिक दलों, प्रशासनिक अधिकारियों आदि को राहत मिलेगी। इसके साथ विकास कार्यों में बार-बार पैदा होने वाले गतिरोध से मुक्ति मिलेगी। मगर व्यावहारिक स्तर पर ऐसा करा पाना बहुत कठिन है। नीति आयोग ने सुझाव दिया था कि देश भर में चुनाव एक साथ कराए जाने चाहिए। इसके लिए कुछ विधानसभाओं के कार्यकाल में विस्तार और कुछ के कार्यकाल में कटौती करने की जरूरत पड़ सकती है। मगर दिक्कत यह है कि जिन विधानसभाओं के कार्यकाल कुछ समय पहले ही शुरू हुए हैं, उन्हें फिर से नए चुनाव में धकेल देने से विवाद की गुंजाइश बनी रहेगी। इसलिए संसद की स्थायी समिति ने कहा था कि आधी विधानसभाओं के चुनाव लोकसभा के साथ कराए जाएं और बाकी के लोकसभा की मध्यावधि में। यह सुझाव काफी हद तक व्यावहारिक माना जा रहा है। मगर लोकसभा और विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराने में कई सैद्धांतिक और वैधानिक दिक्कतें भी हैं। विधानसभाओं के चुनाव स्थानीय मुद्दों पर लड़े जाते हैं, जिनमें लोग पार्टी के बजाय कई बार स्थानीय नेता या क्षेत्रीय दलों को उनके कामकाज के आधार पर तरजीह देते हैं। लोकसभा के साथ उनके चुनाव कराने से न सिर्फ लोगों के सामने भ्रम की स्थिति पैदा होगी, बल्कि इससे राज्यों के राजनीतिक अधिकारों में भी बाधा उत्पन्न होगी, जोकि संघीय ढांचे के अनुरूप नहीं होगा। फिर सबसे बड़ी अड़चन यह है कि देश भर में एक साथ चुनाव कराने को लेकर संविधान में कोई नियम नहीं है, इसलिए इसके लिए संविधान संशोधन करना होगा, जो कि मौजूदा स्थितियों में संभव नहीं लग रहा। यह सही है कि अगर लोकसभा और विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराने की व्यवस्था बनती है तो चुनाव खर्च और भ्रष्टाचार में काफी हद तक कमी आएगी और प्रशासन को बेवजह परेशानियों से मुक्ति मिलेगी और वह विकास कार्यों पर अपना ध्यान केंद्रित कर सकेगा। पर यह इस बात की गारंटी नहीं है कि दोनों चुनाव एक साथ कराने की व्यवस्था कितने समय तक बनी रह पाएगी। किन्हीं स्थितियों में अगर लोकसभा या कोई विधानसभा कार्यकाल पूरा होने से पहले ही भंग हो जाती है, तो उसका मध्यावधि चुनाव लंबे समय तक टालना संभव नहीं होगा।

सभी दल चुनाव के लिए तैयार हो रहे, पर विकास का रोडमैप किसी के पास नहीं

जैसे-जैसे 2019 में होने वाले आम चुनाव नजदीक आते जा रहे हैं वैसे-वैसे राजनीतिक सरगर्मियां तेज होती जा रही हैं। संभवतः आजादी के बाद यह पहला आम चुनाव होगा, जिसके लिये इतनी अग्रिम चुनावी सरगर्मियां देखने को मिल रही हैं। न केवल भाजपा बल्कि सभी राजनीतिक दलों में आम चुनाव का माहौल गरमा रहा है। अपने-अपने प्रान्तों में लोग वर्तमान नेतृत्व का विकल्प खोज रहे हैं जो सुशासन दे सके। सभी पार्टियां सरकार बनाने का दावा पेश कर रही हैं और अपने को ही विकल्प बता रही हैं तथा मतदाता सोच रहा है कि देश हो या राज्य-नेतृत्व का निर्णय मेरे मत से ही होगा। साल 2019 के आम चुनाव में अमित शाह और नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली ताकतवर बीजेपी का सामना करने के लिए कांग्रेस समेत विपक्ष के कई दलों ने एक साथ आने के लिए तैयारियां शुरू कर दी हैं। देश के तमाम विपक्षी दल इस समय ह्यफासीवादह्न से लेकर सांप्रदायिकता से लड़ने की बात कह रहे हैं। इस मुद्दे पर सभी दलों में आपसी सहमति दिखाई भी दे रही है। लेकिन क्या इस सहमति के साथ विपक्ष पूरी ताकत के साथ बीजेपी का सामना करने में सक्षम होगा? बीजेपी के खिलाफ जिस विपक्ष को बनाने की कोशिशें हो रही हैं उसकी सबसे बड़ी कमजोरी है एक ऐसे नेता की कमी जिसे पूरा विपक्ष अपना नेता मानने के लिए तैयार हो और जिसे देश भी स्वीकार करे। एक बड़ी कमजोरी यह भी है कि विपक्ष के पास कोई कार्यक्रम नहीं है जिसे वह देश के सामने पेश कर सके। नोटबंदी से लेकर जीएसटी पर सरकार की फजीहत होने के बाद भी विपक्ष देश के सामने कोई सार्थक भूमिका पेश नहीं कर सका। सीएसडीएस की सर्वे में एक्जिट पोल के आधार पर राष्ट्रीय राजनीति में व्यापक बदलाव होने के संकेत मिलते हैं। अखिलेश यादव द्वारा बीबीसी को दिया गया इंटरव्यू यह दशार्ता कि 2019 के लोकसभा चुनाव की रणनीति अभी से तैयार हो रही है। तैयारी अच्छी बात है लेकिन किस चीज की ? जीतना बड़ी बात नहीं है, लेकिन उद्देश्यों के साथ जीतना बड़ी बात है। दरअसल समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और बहुजन समाज पार्टी जैसे गैर एनडीए राजनीतिक दल नरेन्द्र मोदी के बढ़ते हुए ग्राफ को लेकर चिंतित हैं और साल 2019 के लोकसभा चुनाव के लिए चक्रव्यूह तैयार करना चाहते हैं। राष्ट्रीय स्तर पर मोदी के खिलाफ लामबंद होना आसान काम नहीं है। मायावती, अखिलेश यादव, नीतीश कुमार, ममता बनर्जी और कांग्रेस के बीच विरोधाभास बहुत ज्यादा है। व्यक्तित्व में असमानता, अपने आप पर शक्तिशाली होने का अहंकार, कार्यकताओं को इकट्ठा न कर पाना और जातीय समीकरण कुछ ऐसे बिंदु हैं जहां मोदी विरोधी लाख कोशिश करने के बावजूद भी लामबंद नहीं हो पा रहे हैं। सबसे बड़ी विडम्बना यह है कि मोदी के द्वारा खींची गयी बड़ी लकीरों को छोटा करने का कोई उपाय किसी राजनीतिक दल के पास नहीं है। एक बड़ी विडम्बना यह भी है कि देश की बढ़ती समस्याओं से निजात दिलाने का कोई ठोस कार्यक्रम भी किसी राजनीतिक दल के पास नहीं है। आज देश को एक सफल एवं सक्षम नेतृत्व की अपेक्षा है, जो राष्ट्रहित को सर्वोपरि माने। आज देश को एक अर्जुन चाहिए, जो मछली की आंख पर निशाने की भांति भ्रष्टाचार, राजनीतिक अपराध, महंगाई, बेरोजगारी, बढ़ती आबादी, प्रदूषण, महिला अपराध, व्यापार की डांवाडोल स्थितियों आदि समस्याओं पर ही अपनी आंख गड़ाए रखें। देश की वर्तमान राजनीति विसंगतियों एवं विषमताओं से ग्रस्त है। भ्रष्टाचार, घोटाले और राजनीतिक अपराध की बढ़ती स्थितियों पर कोई भी दल बुनियादी कार्यक्रम प्रस्तुत करने में असफल है। भले ही अपनी जीत को सुनिश्चित करने के लिये राजनीतिक दल ईमानदार और पढ़े-लिखे, योग्य लोगों को उम्मीदवार बनायेंगे, लेकिन इन सबके बावजूद सुधार की अवधारणा अभी संदिग्ध ही दिखाई देती है। फिर भी हम कैसे आशा करें कि कोई गांधी या कोई जेपी के रास्ते पर चलते हुए राजनीति की विकृतियों से छुटकारा दिला देंगे। हमें सम्पूर्ण क्रांति की नहीं, सतत क्रांति की आवश्यकता है। सम्पूर्ण राष्ट्र के राजनीतिक परिवेश एवं विभिन्न राजनीतिक दलों की वर्तमान स्थितियों को देखते हुए बड़ा दुखद अहसास होता है कि किसी भी राजनीतिक दल में कोई अर्जुन नजर नहीं आ रहा जो मछली की आंख पर निशाना लगा सके। कोई युधिष्ठिर नहीं जो धर्म का पालन करने वाला हो। ऐसा कोई नेता नजर नहीं आ रहा जो स्वयं को संस्कारों में ढाल, मजदूरों की तरह श्रम करने का प्रण ले सके। जो लोग किन्हीं आदर्शों एवं मूल्यों के साथ राजनीति में उतरे थे परन्तु राजनीति की चकाचौंध ने उन्हें ऐसा धृतराष्ट्र बना दिया कि मूल्यों की आंखों पर पट्टी बांध ये सब एक ऐसे सेनानायक के निदेर्शों की छांव तले अतीत में अपने जीवन की भाग्यरेखा तलाशते रहे। सभी राजनीतिक दलों में आंतरिक लोकतंत्र का अभाव है और परिवारवाद तथा व्यक्तिवाद की छाया है। कोई अपने बेटे को प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहती हैं तो कोई अपने बेटे को मुख्यमंत्री के रूप में। किसी का पूरा परिवार ही राजनीति में है, इसलिए विरासत संभालने की जंग भी जारी है। नये-नये नेतृत्व उभर रहे हैं लेकिन सभी ने देश-सेवा के स्थान पर स्व-सेवा में ही एक सुख मान रखा है। आधुनिक युग में नैतिकता जितनी जरूरी मूल्य हो गई है उसके चरितार्थ होने की सम्भावनाओं को उतना ही कठिन कर दिया गया है। ऐसा लगता है मानो ऐसे तत्व पूरी तरह छा गए हैं। खाओ, पीओ, मौज करो। सब कुछ हमारा है। हम ही सभी चीजों के मापदण्ड हैं। हमें लूटपाट करने का पूरा अधिकार है। हम समाज में, राष्ट्र में, संतुलन व संयम नहीं रहने देंगे। यही आधुनिक सभ्यता का घोषणा पत्र है, जिस पर लगता है कि हम सभी ने हस्ताक्षर किये हैं। भला इन स्थितियों के बीच वर्ष 2019 के आम चुनावों में हमें वास्तविक जीत कैसे हासिल हो ? आखिर जीत तो हमेशा सत्य की ही होती है और सत्य इन तथाकथित राजनीतिक दलों के पास नहीं है।

महाभारत युद्ध में भी तो ऐसा ही परिदृश्य था। कौरवों की तरफ से सेनापति की बागडोर आचार्य द्रोण ने संभाल ली थी। एक दिन दुर्योधन आचार्य पर बड़े क्रोधित होकर बोले- गुरुवर कहां गया आपका शौर्य और तेज? अर्जुन तो हमें लगता है समूल नाश कर देगा। आप के तीरों में जंग क्यों लग गई। बात क्या है? आज लगभग हर राजनीतिक दल और उनके नेतृत्व के सम्मुख यही प्रश्न खड़ा है और इस प्रश्न का उत्तर उन्हीं के पास है।

राजनीति की दूषित हवाओं ने हर राजनीतिक दल और उसकी चेतना को दूषित कर दिया है। सत्ता और स्वार्थ ने अपनी आकांक्षी योजनाओं को पूर्णता देने में

कांग्रेस मेवा दल (व्यंग्य)

आजादी से पहले 'कांग्रेस सेवा दल' नामक एक स्वयंसेवी दल होता था। उसका काम कांग्रेस की सभा, सम्मेलन और अधिवेशनों में सफाई, दरी बिछाना, माइक लगाना, मंच सजाना और बड़े नेताओं के कपड़े आदि धोना होता था। आजादी के बाद कांग्रेस को सत्ता मिल गयी। अतः सेवा का काम सरकारी कर्मचारी करने लगे। सेवा दल में जिनकी पहुंच ऊपर तक थी, वे टिकट पाकर बड़े नेता हो गये। बाकी लोग दलाली, रिश्वत और ठेकेदारी जैसे स्थानीय महत्व के काम में लग गये।

एक समय संजय गांधी ने मारुति कंपनी की तर्ज पर 'सेवा दल' और 'यूथ कांग्रेस' को पुनर्जीवित किया था; पर उनके सम्मेलन के समय बाजार बंद रहते थे। 'यूथ कांग्रेस मेल' के स्टेशन पर आने से पहले खोमचे वाले सामान सहित बाहर चले जाते थे। सुना है नागपुर अधिवेशन के समय लालबत्ती क्षेत्र में कई यूथ पिटे थे। चूंकि वे फोकट में ही मस्ती करना चाहते थे। अतः लोग 'यूथ कांग्रेस' को 'लूट कांग्रेस' कहने लगे।

संजय के बाद सौम्य चेहरे वाले राजीव गांधी का दौर आया। अपनी मां की हत्या से प्राप्त सहानुभूति के कारण उन्हें इतनी सीट मिल गयीं कि सेवा दल और यूथ कांग्रेस की जरूरत ही नहीं रही; पर बोफोर्स दलाली ने उनकी नैया डुबो दी।

उसके बाद से कांग्रेस को अपने बल पर कभी बहुमत नहीं मिला। 2014 की आंधी में तो बेचारे इतने सिकुड़ गये कि उन्हें विपक्ष का दर्जा भी नहीं मिला। भगवान किसी को ऐसी कंगाली न दे।

पर अब फिर युद्ध के बाजे बज रहे हैं। बड़े-बड़े होटलों में खाने और पीने के दौर के साथ गठबंधन की चचार्एं हो रही हैं। मम्मीश्री ने राहुल बाबा को समझा दिया है कि अगर कांग्रेस के खाते में अपनी 200 सीट नहीं आयीं, तो बाकी चिल्लर को जोड़ने से भी प्रधानमंत्री की कुर्सी नहीं मिलेगी। इसलिए वे यूथ कांग्रेस और सेवा दल को जगा रहे हैं।

शर्मा जी इससे बहुत खुश हैं। उन्हें लगता है कि अब पार्टी के दिन चढ़ने ही वाले हैं। एक बार दिल्ली में सरकार बनी, तो फिर राज्यों में भी बहार आते देर नहीं लगेगी। पिछले दिनों कांग्रेस सेवा दल के अध्यक्ष महोदय हमारे शहर में पधारे। पहले तो वे हवाई अड्डे पर ही नाराज हो गये। वे सोचते थे कि कम से कम 250 गाड़ियां और एक हजार लोग उन्हें लेने आएंगे; पर वहां 25 गाड़ी भी नहीं थीं। लोगों ने बता दिया कि केन्द्र से नगर तक, कहीं सरकार न होने से हाथ बहुत तंग है। इसलिए जो है, उसे ही बहुत समझें।

शाम को पार्टी कार्यालय में युवाओं की मीटिंग थी। अध्यक्ष जी ने कहा कि हमें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जैसे समर्पित युवाओं का संगठन बनाना है। इस पर एक युवा नेता बोले कि वहां तो कई साल पैर रगड़ने पड़ते हैं। हमारे बस का ये नहीं है। अध्यक्ष जी ने उन्हें समझाने का प्रयास किया कि हम सेवा दल वाले हैं; पर युवा नेता ने साफ कह दिया कि टिकट का आश्वासन हो, तो हम कुछ सेवा करें। वरना हमें और भी कई काम हैं। कई गुटों के लोग वहां थे। अतः इस बात पर मारपीट होने लगी। जैसे तैसे अध्यक्ष जी वहां से निकले।

अध्यक्ष जी की वापसी की व्यवस्था रेलगाड़ी से की गयी थी। स्टेशन पर शर्मा जी ने उनसे पूछा कि सेवा दल को कुछ टिकट मिलेंगे या चुनाव में उनका उपयोग कर फिर कूड़ेदान में डाल दिया जाएगा?

अध्यक्ष जी के चेहरे पर पीड़ा के बादल घिर आये, ''शर्मा जी, आप पुराने कार्यकर्ता हैं। इसलिए आपसे क्या छिपाना। असल में ये 'सेवा दल' नहीं 'मेवा दल' है। मैं जहां जाता हूं, वहां लोग टिकट की ही बात करते हैं। अभी तक तो मेरा टिकट ही पक्का नहीं है। ऐसे में मैं किसी को क्या आश्वासन दे सकता हूं।

उद्योग विहार
निष्पक्ष गारिक सगाचार पत्र
E-mail : udyogviharnp@yahoo.com

स्वच्छता अभियान के साथ किया गया पौधारोपण कार्यक्रम

गाजियाबाद। मानसून की शुरूआत में उत्थान समिति के चेयरमैन सत्येन्द्र सिंह ने पी सी गुप्ता के सहयोग से शास्त्री नगर के पार्क में स्वच्छता अभियान चलाया एवं पौधारोपण किया। प्रत्येक पौधे की देखभाल के लिए एक ग्रीन वारियर को ज़िम्मेवारी दी गयी। यह बहुत जरूरी है क्योंकि सिर्फ.पौधे लगा देने से कुछ नहीं होगा जब तक उसकी देखभाल उसके वृक्ष बन जाने तक न की जाए । सभी सहयोगियों ने इस कार्यक्रम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया. इस अवसर पर सत्येन्द्र सिंह ने कहा की हमें पर्यावरण को बचने के लिए पौधारोपण करना ही होगा. आज वायुमंडल में

❑ हमें अधिक से अधिक पीपल एवं नीम के पौधे लगाने पर जोर देना चाहिए ताकि वातावरण में ऑक्सीजन की कमी दूर

ऑक्सीजन की कमी हो गयी है जिसे पौधे लगाकर ही पूरा किया जा सकता है अतः हमें अब अत्यंत सचेत होने की जरुरत है क्योंकि हमारे बच्चों का भविष्य खतरे में है अतः अब हमें जागना ही होगा. हमें अधिक से अधिक पीपल एवं नीम के पौधे लगाने पर जोर देना चाहिए ताकि वातावरण में ऑक्सीजन की कमी दूर हो तथा वातावरण शुद्ध हो. इस अवसर पर विनोद भार्गव, हरीश जिंदल, अतुल गुप्ता, एस सी शर्मा, भोपाल सिंह, विपिन शर्मा, पवन कुमार अग्रवाल, सक्सेना, अनिमेष शर्मा, मुकेश दुबे, अमित शर्मा इत्यादि लोगों ने बद चढ़ कर हिस्सा लिया।

संगठन को और धार देगी भारतीय जनता पार्टी

सेक्टर स्तर पर प्रवास करके जांची जाएगी बूथ समितियों की सत्यता

गाजियाबाद। बूथ स्तर तक पार्टी संगठन को मजबूत करने और आगामी लोकसभा चुनाव में 51 प्रतिशत से ज्यादा मत हासिल करने की कवायद में भाजपा संगठन जुट गया है। इसके लिए पार्टी संगठन ने 30 जुलाई तक एक बूथ कमेटियों की सत्यता जांचने के लिए अभियान शुरू किया है। अभियान में कही कोई कमी न रहे इसके लिए गाजियाबाद में वरिष्ठ भाजपाइयों की डयूटी लगाई है। जिसमें केंद्रीय राज्यमंत्री जनरल वीके सिंह,राज्यमंत्री अतुल गर्ग समेत तमाम विधायकों, पूर्व विधायकों व पूर्व सांसदों,पार्षदों समेत तमाम वरिष्ठ भाजपाइयों की डयूटी लगाई है। जो सेक्टर स्तर पर

जाकर प्रवास करेंगे और बूथ समितियों की सत्यता को जांचेंगे। जैसे-जैसे लोकसभा

❑ वीके सिंह, अतुल गर्ग समेत तमाम विधायकों की लगी डयूटी

चुनाव नजदीक आ रहा है और विपक्ष से महागठबंधन की चुनौती मिल रही है वैसे-वैसे भाजपा संगठन को लेकर गंभीर होती जा रही है। पार्टी को बूथ स्तर तक शतप्रतिशत मजबूत करने के लिए पार्टी ने एक अभियान शुरू किया है जो 30 जुलाई तक चलेगा। इस अभियान के दौरान न केवल बूथ कमेटियों की सत्यता की जांच की जाएगी बल्कि एक बूथ पर दस अनुसूचित जाति व 10 पिछड़े वर्ग के सदस्य बनाने का लक्ष्य पार्टी ने दिया है।

साथ ही इस अभियान के दौरान तमाम बूथ समितियों की सत्यता की जांच भी की जाएगी। इसके लिए मंत्री,सांसद, विधायक, पूर्व विधायक, पूर्व सांसद, पार्षद व भाजपा से लंबे समय से जुड़े वरिष्ठ नेताओं की डयूटी लगाई गई है। ये नेता एक दिन सेक्टर स्तर पर जाकर प्रवास करेंगे तथा बूथ समितियों की सत्यता की जांच गंभीरता पूर्वक करेंगे। साथ ही इनको यह भी जिम्मेदारी सौंपी गई है कि प्रत्येक बूथ पर 10 सदस्य अनुसूचि जाति व 10 पिछड़े वर्ग से ताल्लुक रखने वाले लोगों को सदस्य बनाया जाए।

डा.प्रविंद्र सिंह को इस अभियान को प्रभारी बनाया गया है। जबकि महानगर महामंत्री राजेश त्यागी, सुरेंद्र नागर, लेखराज माहौर व राजीव अग्रवाल को मंडल प्रभारी बनाया गया है।

गाजियाबाद महानगर में कुल 1835 बूथ समिति हैं जबकि 17 मंडल हैं। राजेश त्यागी को पांच जबकि सुरेंद्र नागर, लेखराज माहौर व राजीव अग्रवाल को चार-चार मंडल सौंपे गए हैं। महानगर में कुल 148 सेक्टर हैं। मंडल प्रभारी राजेश त्यागी ने बताया कि अभियान शुरू कर दिया गया है और 30 जुलाई तक पूरा कर लिया जाएगा।

पेट्रोल-डीजल की कीमतों से बढ़ गई खुदरा महंगाई दर, औद्योगिक उत्पादन में भी दिखी गिरावट

मई में भी ज्यादा थे फल-सब्जियों के दाम

मई महीने में सब्जियों से जुड़ी महंगाई दर 7.29 फीसदी से बढ़कर 8.4 फीसदी हो गई थी। वहीं दालों की महंगाई दर 2.56 फीसदी से बढ़कर 2.78 फीसदी रही थी। केंद्र सरकार की तरफ से आंकड़ों के मुताबिक मई में औद्योगिक उत्पादन दर गिरकर 3.2 फीसदी रह गया। यह अप्रैल में 4.9 फीसदी था।

नई दिल्ली। जून महीने में खुदरा महंगाई दर 5 फीसदी के पार चली गई है। वहीं औद्योगिक उत्पादन में गिरावट देखने को मिली है। केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय (सीएसओ) की तरफ से जारी आंकड़ों के मुताबिक जून महीने में खुदरा महंगाई दर 5 फीसदी हो गई। मई महीने में खुदरा महंगाई बढ़कर 4.87 फीसदी थी, जो पिछले चार महीनों में सबसे अधिक थी।अप्रैल में खुदरा महंगाई दर 4.58 फीसदी थी।

लगातार बढ़ रही है महंगाई दर

पेट्रोल-डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी और फिर गिरावट के बाद भी महंगाई दर में उछाल देखने को मिला। हालांकि इनकी कीमतों में केवल चार दिन गिरावट रही। 26 जून से पेट्रोल-डीजल के दाम गिरना शुरू हुए थे, उससे पहले इनमें लगातार तेजी का दौर बना हुआ था।

आरबीआई ने जताई थी महंगाई की आशंका

इससे पहले भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने जून के पहले हफ्ते में हुई मौद्रिक नीति समिति की तीन दिवसीय बैठक में रेपो रेट को बढ़ाकर 6.25 फीसदी कर दिया था।

बढ़ती महंगाई और अर्थव्यवस्था के सामने खड़ी चुनौतियों की वजह से आरबीआई ने यह फैसला लिया था। आरबीआई ने महंगाई के 4.8 से 4.9 फीसदी के बीच रहने का अनुमान लगाया है। आरबीआई को खुदरा महंगाई दर को चार फीसदी के आसपास रखने की जिम्मेदारी मिली हुई है, लेकिन पिछले चार महीनों के दौरान महंगाई दर इस लक्ष्य से अधिक रही है। खुदरा महंगाई दर के ताजा आंकड़े आने से पहले ब्लूमबर्ग के इकोनॉमिस्ट पोल में इसके 4.9 फीसदी के करीब रहने का अनुमान लगाया गया था।

बाबा रामदेव की पतंजलि अब बेचेगी दूध-दही और फ्रोजन मटर

दिल्ली। योग गुरू बाबा रामदेव की कंपनी पतंजलि अब डेयरी सेक्टर में भी अपना धमाल मचाने के लिए उतरने वाली है। कंपनी अपने कई डेयरी उत्पाद देश के चार राज्यों में लांच करने जा रही है। इसके अलावा छोटे बच्चों के लिए कंपनी ने डायपर भी उतार दिया है। पतंजलि ने डेयरी सेक्टर में जो उत्पाद लांच करने का प्लान किया है उनमें दूध, दही, पनीर, छाछ व फ्रोजन मटर शामिल हैं। कंपनी का दावा है कि सारे उत्पादों में किसी तरह की कोई मिलावट नहीं है और ग्राहकों को शुद्ध उत्पाद मिलेंगे। पतंजलि आयुर्वेद के प्रवक्ता एस के तिजारावाला ने बताया कि लोगों को गाय का शुद्ध दूध और इससे बने उत्पाद अब बहुत ही कम दर पर मिलेंगे। जिन राज्यों में कंपनी ने अपने उत्पादों की बिक्री सबसे पहले शुरू करेगी उनमें दिल्ली, राजस्थान, हरियाणा और महाराष्ट्र शामिल हैं। पतंजलि का मुख्य मुकाबला अमूल, मदर डेयरी, सरस, नमस्ते इंडिया, पारस और गोपालजी जैसी कंपनियों से होगा। दूध की कीमत अन्य कंपनियों के मुकाबले एक से दो रुपये प्रति लीटर कम होगी।

पूर्व सहायक निदेशक कारखाना पर लगाया गया 25 हजार का जुर्माना

गाजियाबाद। पूर्व सहायक निदेशक कारखाना एस एम खालिद के ऊपर रु 25000 /- का जुमार्ना राज्य सूचना आयोग द्वारा लगाया गया। सत्येन्द्र सिंह ने पूर्व सहायक निदेशक कारखाना एस एम खालिद से सूचना का अधिकार 2005 के तहत गाजियाबाद जनपद में प्रतिष्ठानों एवं कारखानों में दुर्घटनाओं के विषय में जानकारी मांगी थी किन्तु उन्होंने नहीं उपलब्ध करवाई थी जिसके कारण खालिद के ऊपर रु 25000 /- का जुमार्ना राज्य सूचना आयोग द्वारा लगाया गया है। अवैध नियुक्ति करवाकर पूर्व सरकार में भ्रष्ट खालिद ने यह पद हासिल किया था जिसे अब पुनः बाबू बना दिया गया है। राज्य सूचना अधिकारी ने आदेश देते हुए यह लिखा है कि प्रस्तुत प्रकरण में जन सूचनाधिकारी गंभीर नहीं है। पत्रावली पर ऐसा कोई साक्ष्य भी उपलब्ध नहीं है, जिससे यह स्पष्ट हो सके कि प्रकरण में जन सूचनाधिकारी द्वारा अपीलकर्ता को उसके मूल आवेदन दिनांक-09.12.2014 के क्रम में वांछित सूचनाएं, सूचना अधिकारी अधिनियम-2005 में निर्धारित समयान्तर्गत 30 दिनों के भीतर उपलब्ध करायी गयी हों। ऐसे में प्रतिवादी जन सूचनाधिकारी/सहायक निदेशक, कारखाना, गाजियाबाद क्षेत्र, गाजियाबाद, एस0एम0 खालिद को अपीलकर्ता को साशय विलंब से सूचनाएं देने का दोषी मानते हुए उनके विरूद्ध सूचना का अधिकारी अधिनियम 2005 की धारा 20(1) के तहत 250 रूपए प्रतिदिन के हिसाब से अर्थदण्ड अधिरोपित करते हुए वसूली का आदेश पारित किया जाता है। अधिरोपित अर्थदण्ड की वसूली जन सूचनाधिकारी/सहायक निदेशक, कारखाना, गाजियाबाद क्षेत्र, गाजियाबाद, श्री एस0एम0 खालिद के जन सूचनाधिकारी के रूप में उनकी कार्यावधि की गणना के आधार पर की जाएगी, किन्तु जन सूचनाधिकारी के वेतन से वसूली जाने वाली अर्थदण्ड की धनराशि रूपए 25,000/- से अधिक नहीं होगी। रजिस्ट्रार, उ0प्र0 सूचना आयोग ने निर्देशित किया है कि वह प्रतिवादी जन सूचनाधिकारी/सहायक निदेशक, कारखाना, गाजियाबाद क्षेत्र, गाजियाबाद, एस0एम0 खालिद के वेतन से अधिरोपित अर्थदण्ड की वसूली कराया जाना सुनिश्चित करें। आयोग द्वारा पारित आदेश की प्रति प्रमुख सचिव/सचिव, श्रम, उ0प्र0 शासन, लखनऊ एवं जिलाधिकारी, गाजियाबाद को अनुपालनार्थ प्रेषित की जाये। इस आदेश के साथ वाद निस्तारित किया जाता है।

आईडीबीआई बैंक के शेयर धारकों के लिए ऑपन ऑफर लाएगी एलआईसी

नई दिल्ली। पिछले दो दिनों में आईडीबीआई बैंक के शेयरों में 16 फीसदी का जबरदस्त उछाल देखने को मिला है. बैंक के शेयरों में यह उछाल एलआईसी के उस प्रस्ताव के बाद आया है, जिसमें उसने बैंक के माइनोरिटी शेयरहोल्डर्स को हिस्सेदारी खरीदने को लेकर खुला ऑफर देने की बात कही है. एक सरकारी अधिकारी ने बिजनेस स्टैंडर्ड को बताया, एलआईसी एक ओपन ऑफर लाएगी, जो माइनोरिटी शेयरहोल्डर्स के हित में होगा. ये वो शेयरहोल्डर्स होंगे, जिनके पास आईडीबीआई बैंक के 8 फीसदी से ज्यादा शेयर हैं. सरकार इसमें भाग नहीं लेगी. इस व्यवस्था के तहत अधिग्रहण करने वाली कंपनी को मौजूदा शेयरधारकों को कंपनी में अतिरिक्त हिस्सेदारी खरीदने के लिए एक प्रस्ताव देना होगा. इसका उद्देश्य उन निवेशकों को बाहर निकलने का मौका भी देना है, जो भी इस सौदे से सहज नहीं हैं. सूत्रों के मुताबिक, सरकार के स्वामित्व वाले बैंक में प्रस्तावित हिस्सेदारी हासिल करने के लिए एलआईसी अपने बोर्ड से मंजूरी मिलने के बाद सेबी से संपर्क करेगा.

कागज पर ये सौदा दोनों पक्षों के लिए जीत की स्थिति की तरह लगता है. एलआईसी बैंकिंग सेक्टर में प्रवेश करने और आईडीबीआई बैंक में बड़ी हिस्सेदारी हासिल करने की उम्मीद कर रहा है. वहीं, आईडीबीआई को उम्मीद है कि इससे उसकी बैलेंस शीट पर कर्ज का बोझ कम होगा. एलआईसी की इस सौदे से लगभग 2,000 बैंक शाखाओं तक सीधी पहुंच होगी, जिसके जरिये वह अपने उत्पादों को बेच सकेगा.

नरम वैश्विक संकेतों, कमजोर मांग से सोने की गिरावट जारी, चांदी भी टूटी

नई दिल्ली। सोने में लगातार गिरावट जारी है और आज फिर सोने की कीमतों में गिरावट दर्ज की गई है. आज भी लोकल ज्वैलर्स की कमजोर मांग के बीच नरम वैश्विक संकेतों से दिल्ली सरार्फा बाजार में सोना 30 रुपये गिरकर 31,350 रुपये प्रति 10 ग्राम पर आ गया. कारोबारियों ने कहा कि नरम वैश्विक संकेतों और चीन और अमेरिका के बीच छिड़े ट्रेड वॉर की वजह से डॉलर के मजबूत होने से सेंटीमेंट कमजोर बने रहे. घरेलू हाजिर बाजार में स्थानीय आभूषण निमार्ताओं और खुदरा विक्रेताओं की मांग कमजोर रहने से भी कीमतों पर दबाव रहा.

आप भी हो सकते हैं 'सिम स्वैप' फ्रॉड का शिकार, इससे बचने के लिए ये बातें जान लीजिए

दिल्ली। सिम स्वैप इन दिनों सबसे बड़े साइबर-फ्रॉड के तौर पर सामने आया है. दिल्ली, बैंगलोर और कोलकाता में कार्ड स्वैप के की मामले सामने आए हैं. इस नई धोखा-धड़ी का शिकारस्मार्टफोन यूजर्स हो रहे हैं, जिनसे महज मिनटों में पैसे लूट लिए जा रहे हैं. शहरों में रहने वाले कई लोग जो डिजिटल प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करते हैं वो इसतरह के फ्रॉड का शिकार हो रहे हैं. यहां तक कि कुछ यूथ भी इस तरह के धोखे में अपने पैसे गवां चुके हैं. सिम स्वाइप फ्रॉड करने के कई तरीके हैं अगर आप भी स्मार्टफोन यूजर है और इस घोखे से बचना चाहते हैं तो ये बातें जान लीजिए. सिम स्वैप एक मोबाइल नंबर पर नया सिम निकालने की प्रकिया है. दरअसल फ्रॉड करने वाले आपके नंबर पर एक नया मोबाइल नंबर निकलते हैं. ऐसा होने पर आपका सिमकार्ड

काम करना बेद कर देता है और आपका नंबर इनवैलिड हो जाता है. इस तरह धोखाधड़ी करने वाले के पास आपका नंबर आ जाता है और इसकी मदद से आसानी से ओटीपी यानी वन टाइम पासवर्ड का बैंक ट्रांजैक्शन या कोई भी ट्रांजैक्शन कर के लोगों का नुकसान किया जा सकता है. सिम स्वैप फ्रॉड का सबसे आसान तरीका है एक कॉल से शुरू होता है. आपको एक कॉल आएगा जिसमें वो आपको आपके टेलीकॉम कंपनी (एयरटेल, वोडाफोन, जियो, आइडिया) का एग्जीक्यूटिव बताएंगे. इस फोन को रुटीन कॉल बताएंगे साथ ही नेटवर्क बेहतर बनाने के लिए आपसे आपको फोन नंबर मांगेंगे. इतना ही नहीं ये लोग आपको फोन पर बेहतर डेटा ऑफर और नए प्लान देने की बात भी करते हैं जिसके झांसे में कोई भी आसानी से आ सकता है. स्कैम कॉलर आपको फोन करके चाहेगा कि वह आपके सिम पर प्रिंट 20 डिजिट वाला नंबर पा सके. हर सिम पर एक 20 डिजिट का नंबर होता है जिसे आप अपनी सिम पर भी पीछे की ओर जांच सकते हैं. स्कैम करने वाले चाहते हैं ति आप ये 20 डिजिट वाला नंबर उनके साथ साझा करें. इसके लिए वो की नए ऑफर की पेशकश करते हैं लेकिन भूल कर भी ऐसा ना करें. अगर आप अपना यूनिक 20 डिजिट वाला सिम नंबर स्कैम करने वाले से साझा करते हैं तो वह आपको 1 दबाने की सलाह देगा. ये सिम स्वैप को सहमति देने के लिए होगा. आपके यूनीक नंबर से वह टेलीकॉम कंपनी को सिम स्वैप के आवेदन करेगा. आप 1 बटन दबाएंगे तो इसतरह आप अपने सिम स्वैप के लिए सहमत हो जाएंगे. टेलीकॉम कंपनियों को लगेगा ये रिक्वेस्ट आपकी ओर की गई है. इसतरह आपका नंबर हाईजैक कर लिया जाएगा. इस तरह के मामलों में आपका बैंक अकाउंट का आईडी और पासवर्ड स्कैम करने वालों के पास पहले से मौजूद होता है बात सिर्फ ओटीपी पर आ कर अटकती है और सिम स्वैप के जरिए धोखाधड़ी कपने वाले लोग आपका ओटीपी भी पा लेते हैं और आपके अकाउंट से पैसे ले उड़ते हैं.

उद्योग विहार
निष्पक्ष गारिक रागाचार पत्र
राष्ट्रीय
07
P.
E-mail : udyogviharnp@yahoo.com
गाजियाबाद, जुलाई, 2018

एलिवेटेड रोड को लेकर बीजेपी पार्षद ने फिर उठाए सवाल

रोड के बनने पर लागत पहुंचेगी पांच सौ करोड से ज्यादा

बीजेपी पार्षद ने कहा जीडीए खुद से एलिवेटेड रोड बनाने पर ना दे जोर

गाजियाबाद। घंटा घर से भाटिया मोड के बीच प्रस्तावित एलिवेटेड रोड डिजाइन में बदलाव एवं लागत में बढौतरी के पहलू पर एक बार फिर से नगर निगम से बीजेपी के पार्षद एवं जीडीए बोर्ड के पूर्व सदस्य राजेंद्र त्यागी ने सवाल खडे किए है। श्री त्यागी ने कहा कि गाजियाबाद विकास प्राधिकरण को चाहिए कि एक बार एलिवेटेड रोड का निर्माण कार्य आरंभ करने से पहले आमजनता से आपत्ति आमंत्रित करनी चाहिए और इसके साथ साथ खुद से एलिवेटेड रोड का निर्माण कार्य करने के बजाय किसी दूसरी एजेंसी को तय करना चाहिए।

जीडीए के द्वारा बनाए जाने वाले भवनों के दौरान गुणवत्ता पर नहीं दिया जाता है ध्यान

श्री त्यागी ने कहा कि जीडीए घंटाघर से भाटिया मोड तक एलिवेटेड रोड को लेकर ना जाने किन वजह से जल्द बाजी दिखा रहा है उनकी समझ से दूर है। उन्होंने कहा जिस वक्त सीपीडब्लूडी के द्वारा रिपोर्ट एवं लागत से जुडी रिपोर्ट प्राधिकरण के हवाले की थीं उस वक्त कहा गया था कि लागत अधिक है। जीडीए खुद से एलिवेटेड रोड का निर्माण करेगा। श्री त्यागी ने कहा कि जो जीडीए दावा कर रहा है कि एलिवेटेड रोड पर 253 करोड रूपए की लागत आएगी वह पांच सौ करोड रूपए से ज्यादा बैठनी तय है। उन्होंने ये भी पहलू उठाया कि अभी तक जीडीए के द्वारा जिन भी आवासीय इमारतों का निर्माण किया उनकी गुणवत्ता क्या है वह किसी से छिपी नहीं है। ज्यादातर आवासीय इमारतें खंडहर में तब्दील हो गई है। एक दशक पहले वैशाली सेक्टर दो कामना एवं इससे पहले इंदिरापुरम में निमार्णाधीन इमारत के गिरने की घटनाएं हो चुकी है। नेहरू विकास मीनार जिसे बनाने पर एक बडी रकम खर्च की गई उसे गिराना पडा।

झमाझम बारिश से मौसम हुआ खुशगवार

गाजियाबाद। शनिवार की सुबह हुई झमाझम बारिश से मौसम खुशगवार हो गया। लेकिन कुछ स्थानों पर जल भराव की समस्या से लोग परेशान रहे। शनिवार को सुबह करीब दस बजे से बारिश शुरू हुई जो कि दोपहर रूक रूक कर जारी थी। बारिश से जहां किसानों के चेहरे खिले है वहीं लोगों को उमस भरी गर्मी से कुछ राहत मिली है। लेकिन कुछ मोहल्लों में जलभराव की समस्या बन गई। जिसकी वजह नाले-नालियों की पूरी तरह सफाई न होना तथा संकरा होना बताया जा रहा है। वहीं नगर पालिका ईओ जेके आनंद ने बताया कि नालों की सफाई का काम युद्ध स्तर पर किया जा रहा है। यदि कही जलभराव की समस्या है तो उसकी सूचना नगर पालिका को दे। नगर पालिका जलभराव को समाप्त करेंगी।

नगर निगम करेगा सफाई कर्मचारियों की छंटनी

गाजियाबाद। जहां तमाम प्रयास के बाद भी शहर के आंतरिक हिस्सों में सफाई व्यवस्था सुधर नहीं पा रही है ठीक दूसरी तरफ नगर निगम प्रशासन कर्मचारियों की संख्या ज्यादा मानते हुए अब उनकी छटनी की तैयारी में जुट गया है। इसके साथ साथ जिन वार्डों में क्षमता से ज्यादा कर्मचारी है उन्हें ऐसे वार्ड में तैनात करने की कबायद तेज हो गई है जहां पर कम कर्मचारी है। इसके लिए निगम का हेल्थ विभाग डाटा को अंतिम रूप देने में जुट गया है।

निगम के हैल्थ विभाग से पता चला कि तमाम अध्ययन के बाद तैयार की गई सूची में साफ हुआ कि पूरे निगम सीमा क्षेत्र में शहर की सफाई व्यवस्था में 2883 कर्मचारी लगे हुए है। इनमें से सिटी जोन में 946,कविनगर जोन में 590 एवं विजय नगर जोन में 444 तथा वसुंधरा जोन में 332 तथा मोहन नगर जोन में 571 कर्मचारियों की सेवाएं ली जा रही है। माना जा रहा है कि सिटी जोन में 141 कविनगर जोन में 66 तथा विजय नगर जोन में 116 तथा मोहन नगर जोन में 24 कर्मचारी क्षमता से ज्यादा है,जबकि वसुंधरा जोन के लिए 228 कर्मचारी और चाहिए। इस आंकडे को 2011 की जनसंख्या के आधार पर माना जा रहा है।

निगम सूत्रों का कहना है कि हेल्थ विभाग के द्वारा तर्क दिया जा रहा है कि साल 2011में केवल 17 लाख की जनसंख्या थीं जबकि अब इससे कई गुणा अधिक हो गई है। मौजूदा जनसंख्या के आधार पर कर्मचारियों की मौजूदा संख्या कुछ भी नहीं है। ये भी खुलासा हुआ कि वसुंधरा जोन के तहत आने वाले वार्ड 89 में मात्र आठ कर्मचारी है जबकि भोवापुर व प्रहलाद गढी में 13-13 कर्मचारी है वार्ड 54 वसुंधरा सैक्टर 1 से 11 के बीच मात्र 15 कर्मचारी है इन तमाम वार्डों में कर्मचारियों की संख्या बढानी होगी।

मामला वसुंधरा का

सीएम कार्यालय के आदेश भी बेअसर

अवैध निर्माण पर एक्शन नहीं

गाजियाबाद। जिले में अवैध निर्माण पर कभी लगाम लग पाएगी इसकी दूर तक भी संभावना नजर नहीं आ रही है। आवास एवं विकास परिषद के कुछ अधिकारियों पर प्रदेश सरकार के द्वारा कार्रवाई सुनिश्चित किए जाने के बाद भी किसी तरह का खौफ दिखाई नहीं दे रहा है। जहां परिषद के अधिकारी नाले को पाटते हुए अवैध तरह से खडी इमारत पर किसी तरह की कार्रवाई नहीं कर पा रहे है वहीं कुछ कदम दूरी पर मौजूदा में खडी की जा रही इमारत से परिषद के अधिकारी अनभिज्ञ दिखाई दे रहे है। परिषद के जानकारों की मानें तो प्रदेश में योगी सरकार के सत्ता में आने के बाद अवैध निर्माण के रेट बढ गए है जहां पर छत एक लाख रूपए वसूल किए जाते थे वहीं इन दिनों दो से ढाई लाख रूपए की वसूली की जाती है। बताते है कि जिस बिल्डर के द्वारा मौजूदा में इमारत का निर्माण किया जा रहा है निर्माण सामग्री से सडक पर भी अवैध कब्जा कर लिया है। निर्माण सामग्री सडक पर देखी जा सकती है कुछ कदम दूरी पर निगम का वसुंधरा जोन कार्यालय होने के बावजूद निगम के अधिकारी भी अनजान है। बताया गया कि वसुंधरा सेक्टर 12 के फ्रैंडस सौसाइटी के भूखंड संख्या 528 के हिस्से को व्यवसायिक में तब्दील किए जाने एवं नाले पर भी अवैध कब्जा किए जाने का मामला सामने आने पर परिषद के अधिकारियों के द्वारा अवैध घोषित करते हुए तोडने के आदेश जारी किए थे, हैरत का पहलू ये है किइस पूरे मामले को फाइलों में कैद कर दिया गया। जबकि इस मामले की गूंज सीएम कार्यालय तक हुई तथा सीएम कार्यालय से कार्रवाई के आदेश भी जारी हुए थे। रेजीडेंट एसोसिएशन के अधिकारियों का कहना है कि आवास एवं विकास परिषद भ्रष्टाचार के केंद्र में तब्दील होकर रह गया है। अवैध तरीके डलने वाली छत के एवज में दो दो लाख रूपए की वसूली की जाती है। सोसाइटी के पदाधिकारियों का कहना था कि इसी इमारत से कुछ कदम की दूसरी पर एक नए बिल्डर के द्वारा इमारत का निर्माण किया जा रहा है। तमाम निर्माण सामग्री सडक पर डाल दी गई है। निर्माण सामग्री के चलते हर वक्त हादसे का खतरा रहता है। एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने पुनः मुख्य मंत्री से अवैध निर्माण के लिए जिम्मेदार अधिकारियों पर एक्शन लिए जाने की मांग की है।

एलिवेटेड रोड के पिलर को नए रूप देने में जुटी एनजीओ

गाजियाबाद। यदि आप गाजियाबाद से हिंडन नहर के साथ लगी रोड से दिल्ली अथवा गाजियबाद लौट रहे है तो आपकों हिंडन के साथ बनायी गई एलिवेटेड रोड के पिलर नए रूप में दिखाई देंगे। कई एनजीओ के द्वारा एलिवेटेड रोड के पिलर को नया रूप देने का काम तेज कर दिया गया है। गणेश जी की अनेक तरह की आकृर्तियां बनायी जा रही है। एनजीओ के सदस्यों का कहना था कि पिलर पर नया रूप देने से पहले एलिवेटेड रोड पर संस्था के द्वारा तरह तरह की आकृतियां बनायी गई थीं। एलिवेटेड रोड पर आकृतियां बनाए जाने का काम पूरा होने के बाद अब पिलर को नया रूप देने का काम किया जा रहा है। प्रयास ये है कि पिलर पर एक बार नजर जाने के बाद वह हटे नहीं। जीडीए के उधान अधिकारी गोविंद सिंह का कहना था कि प्राधिकरण उपाध्यक्ष के आदेश के क्रम में नहर के साथ ग्रीन बेल्ट को भी हरा भरा किया जा रहा है।

राकेश सिन्हा समेत चार चेहरे जाएंगे राज्यसभा, राष्ट्रपति ने किया मनोनीत

नई दिल्ली। राज्यसभा के लिए चार नए सदस्य मनोनीत किए गए हैं. जिसमें आरएसएस विचारक राकेश सिन्हा, किसान नेता राम शकल, मूर्तिकार रघुनाथ माहापात्रा और क्लासिकल डांसर सोनस मानसिंह के नाम हैं। इन चारों को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने मनोनीत किया है।

दरअसल फिलहाल 245 सदस्यीय राज्यसभा में चार सीटें खाली थीं, जो राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत होने थे. अब केंद्र सरकार की सिफारिश पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने इन सदस्यों को राज्यसभा सदस्यता के लिए मनोनीत किया है।

पिछले कुछ दिनों से तमाम चेहरों को लेकर कयास लगाए जा रहे थे। लेकिन सरकार ने इन चार नामों का चुनाव कर राष्ट्रपति के पास भेजा था जिस पर कोविंद ने अपनी मुहर लगा दी है। मनोनीत चेहरों में सोनल मानसिंह मशहूर नृत्यांगना है। जबकि रघुनाथ महापात्रा ओडिशा जाने-माने मूर्तिकार हैं। महापात्रा पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण से सम्मानित हैं। रामशकल जाने-माने किसान नेता हैं. राकेश सिन्हा संघ के विचारक हैं और मीडिया तथा सोशल मीडिया मंचों पर प्रखरता के साथ भाजपा और संघ का पक्ष रखने के लिए जाने जाते हैं। राकेश सिन्हा ने संघ संस्थापक डॉ. हेडगेवार की जीवनी लिखी है जिसे भारत सरकार के प्रकाशन विभाग ने प्रकाशित किया है।

उनकी 'राजनीतिक पत्रकारिता' नमक पुस्तक काफी लोकप्रिय हुआ है. गौरतलब है कि इस साल राज्यसभा की जो सीटें खाली हुई है वो फिल्म, खेल, सामाजिक कार्य और कानून से जुड़े हैं. यूपीए सरकार ने फिल्म से रेखा, खेल से सचिन तेंदुलकर, सामाजिक क्षेत्र से अनु आगा और कानून से के पराशरन को मनोनीत कराया था. अब इन्हीं चारों की जगह पर राष्ट्रपति ने ये नए चेहरे मनोनीत किए।

उद्योग विहार

निष्पक्ष गारिक रागाचार पत्र

फिल्म–खेल–जगत

08 P.

E-mail : udyogviharnp@yahoo.com

गाजियाबाद, जुलाई, 2018

फीफा वर्ल्ड कप

क्रोएशिया की जीत से उठे सवाल भारत कब करेगा कमाल?

नई दिल्ली। क्रोएशिया के फीफा वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंचते ही फुटबॉल की दुनिया में हलचल मच गई. सेमीफाइनल में इंग्लैंड के खिलाफ क्रोएशिया की 'चमत्कारिक' जीत ने भारत में भी सुर्खियां बटोरीं.

भारतीय फुटबॉलप्रेमी क्रोएशिया की अभूतपूर्व सफलता की तरफ ललचाई नजरों से देख रहे हैं. सवाल फिर उठ रहा है– आखिर भारत फुटबॉल विश्व कप में क्यों नहीं है.. ? दुनिया की आबादी 7.6 अरब से ज्यादा है. 2018 के विश्वकप में खिलाड़ियों की कुल संख्या 736 है. इनमें भारतीय खिलाड़ियों की संख्या शून्य है. यह 'खालीपन' हर चार साल बाद होने वाले वर्ल्ड कप के दौरान विशाल भारत को सालता है.

क्रोएशिया मध्य और दक्षिण–पूर्व यूरोप का एक छोटा–सा देश है, जिसकी जनसंख्या महज 42 लाख है. इतनी जनसंख्या तो हमारे देश के किसी बड़े शहर की होती है.

मौजूदा वर्ल्ड कप में क्रोएशिया के ही ग्रुप में आइसलैंड की टीम थी. महज 3.34 लाख की जनसंख्या वाले इस छोटे देश ने भी हमें बौना साबित किया हैं. आइसलैंड भले ही ग्रुप स्टेज से आगे न निकल पाया हो, लेकिन वर्ल्ड कप में उसकी मौजूदगी मात्र से हम चौंक जाते हैं.

हम भारत में फुटबॉल के सकारात्मक पक्ष की ओर भी नजर डाल लें. रैंकिंग की बात करें, तो 2014 में भारतीय टीम दुनिया में 170वें नंबर पर थी, जो अब टॉप–100 (97वें नंबर) में है. इंडियन सुपर लीग (आईएसएल), आई–लीग और यूथ लीग भारत में फुटबॉल के आधार को मजबूत कर रही है.

हाल ही में भारत ने इंटरकॉन्टिनेंटल कप फुटबॉल टूनार्मेंट का खिताब जीता. कप्तान सुनील छेत्री के जोशीले प्रदर्शन ने भारतीय फुटबॉल की उम्मीदों को जरूर जगाया है. फीफा के पूर्व अध्यक्ष सेप ब्लेटर ने एक बार कहा था– 'भारत फुटबॉल जगत का सोता हुआ शेर है'. देखना यह होगा कि इस शेर की नींद कब खुलती है और भारतीय फुटबॉल प्रेमियों की उम्मीद कब पूरी होती है.

अब फिल्मों में किस्मत आजमाएंगी क्रिकेटर शमी की पत्नी हसीन जहां

नई दिल्ली। भारतीय क्रिकेटर मोहम्मद शमी की पत्नी हसीन जहां अब बॉलिवुड में अपनी किस्मत आजमाएंगी। हाल ही में खबर आई थी कि एक अच्छा जीवन बिताने और अपनी 3 साल की बेटी को पालने के लिए हसीन जहां ने मॉडलिंग की दुनिया में वापसी की है। अब वह बॉलिवुड में भी कदम रखने जा रही हैं। बता दें कि हसीन जहां को इसका मौका भी मिल गया है और उन्होंने निर्देशक अमजद की अगली फिल्म ह्यफतवाह्न साइन की है।

जानकारी के मुताबिक इस फिल्म में हसीन जहां एक जर्नलिस्ट के किरदार में नजर आएंगी। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक हसीन जहां ने कहा कि मुझे मेरे और मेरे बच्चे के लिए कुछ करना होगा। मुझे कानूनी लड़ाई लड़ने के लिए भी पैसों की जरूरत है। हसीन पहले मॉडल थीं और कोलकाता नाइट राइडर्स की चीयर लीडर भी थीं। उन्होंने 2014 में शमी से शादी करने के बाद मॉडलिंग छोड़ दी थी। बीते दिनों हसीन जहां ने क्रिकेटर मोहम्मद शमी पर कई गंभीर आरोप लगाए थे। हसीन जहां ने शमी और ससुराल के लोगों पर बेवफाई, हत्या के प्रयास और मेरिटल रेप के आरोप लगाए। इन सब आरोपों की जांच चल रही है लेकिन इस बीच हसीन की आर्थिक स्थिति खराब हो गई है।

मैडम तुसाद में लगेगा अनुष्का शर्मा का बोलने वाला पुतला, फैंस से करेंगी बात

नई दिल्ली। बॉलीवुड की क्यूट एक्ट्रेस अनुष्का शर्मा वैसे तो काफी पॉपुलर हैं लेकिन विराट कोहली के साथ शादी के बाद उनकी ब्रैंड वैल्यू में जबरदस्त इजाफा हुआ। तभी तो देश से लेकर विदेश तक अनुष्का के चर्चे हैं और इस कड़ी में अब वो मैडम तुसाद वैक्स म्यूजियम का हिस्सा बनने जा रही हैं। जी हां, सिंगापुर स्थित मैडम तुसाद म्यूजियम ने अनुष्का का पुतला लगाने का फैसला लिया है। जहां अनुष्का बहुत जल्द फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो और ओपरा विनफ्रे के साथ नजर आयेंगी। अनुष्का का पुतला सिंगापुर स्थित मैडम तुसाद म्यूजियम में ऐसा पहला पुतला होगा जो बोल भी सकता है। जी हां, यह मोम की मूर्ति अपने फैंस से बात भी कर सकेगी। खबरों के मुताबिक अनुष्का की जो मूर्ति होगी, उसके हाथ में एक फोन होगा। वह फोन असली होगा और लोग मूर्ति के साथ सेल्फी भी ले सकते हैं। जब भी कोई मेहमान फोन को हाथ लगाएगा, अनुष्का की मूर्ति उनसे बातें करेगी। दिलचस्प बात यह है कि दुनियाभर की चंद नामचीन हस्तियों के स्टेच्यू को ही मैडम तुसाद ने इंट्रैक्टिव फीचर यानि बात करने वाली तकनीक से लैस किया है। अनुष्का से पहले ओपरा विनफ्रे, क्रिस्टियानो रोनाल्डो, लुईस हैमिल्टन की ऐसी मूर्ति बनाई गई है। मैडम तुसाद, सिंगापुर की जनरल मैनेजर एलेक्स वार्ड ने कहा, 'हम अनुष्का शर्मा के साथ काम करने को लेकर उत्साहित हैं। यहां कई परिवार घूमने आते हैं लेकिन भारत से भी कई युवा भी यहां आते हैं।

अनुष्का शर्मा की बोलने वाली मूर्ति के जरिए हमें उन दर्शकों को भी लुभाने का मौका मिलेगा। कई मेहमानों ने उनकी मूर्ति की गुजारिश की है। हमें यकीन है कि उनका स्टेच्यू हमारे म्यूजियम में चार चांद लगा देगा।' बता दें अनुष्का शर्मा इस साल 'परी' जैसी हॉरर फिल्म में दिखाई दी थीं, जिसने बॉक्स ऑफिस पर अच्छी कमाई की थी। साथ ही वो साल 2018 के आखिर में शाहरुख खान के साथ ह्यजीरोह्न में एक खास किरदार निभाती नजर आएंगी।

नेहा धूपिया ने निक और प्रियंका के रिश्ते की ओर किया इशारा

नई दिल्ली। प्रियंका चोपड़ा और निक जोनस की कथित लव अफेयर की चर्चा इन दिनों दुनिया भर में हो रही है। वैसे तो शुरूआत में ये सब केवल अफवाह लग रही थी, लेकिन जैसे–जैसे वक्त बीत रहा है दोनों की एक–दूसरे के साथ मौजूदगी ज्यादा नजर आने लगी है। यह लव बर्ड साथ–साथ पिछले दिनों इंडिया भी पहुंचा और उन्होंने गोवा में एक–दूसरा के साथ कुछ अच्छे वक्त बिताए। इसके बाद दोनों ब्राजील चले गए, जहां प्रियंका अपने इस खास करीबी दोस्त के लिए उस वक्त चियर करती दिखीं, जब वह एक बड़े स्टेज पर परफॉर्म कर रहे थे। यह कोई बड़ी बात नहीं कि निक जोनस की जबरदस्त फैन फॉलोइंग है, जो उनके म्यूज़िक टैलंट के दीवाने हैं, लेकिन यह बात कम ही लोग जानते होंगे कि प्रियंका के अलावा बॉलिवुड में उनकी एक और फैन हैं और वह हैं बॉलिवुड की सेक्सी और स्टाइलिश ऐक्ट्रेस नेहा धूपिया। जहां प्रियंका और निक ने अब तक अपने रिश्ते को लेकर खुलकर कुछ भी नहीं कहा है, वहां उनकी तस्वीरें काफी कुछ बयां कर रही हैं।

मै. लीगल इन्फोशोल्यूशन्स प्रा0लि0, मुद्रक, प्रकाशक एवं सम्पादक **"सत्येन्द्र सिंह"** द्वारा मै. बी.एफ.एल. इन्फोटैक लि. प्रेस, सी–9, सैक्टर–3, नोएडा से छपवाकर बी.ई.–243, (ग्राउण्ड फ्लोर) अवन्तिका, गाजियाबाद से प्रकाशित किया।

फोन : 0120–4122901 / 4108794 **मोबाइल नं. :** 9818036460 / 9818697406 **E-mail :** udyogviharnp@yahoo.com **संस्थापक :** शीतला प्रसाद सिंह **प्रधान सम्पादक :** सत्येन्द्र सिंह **सम्पादक :** बबिता सिंह **सह सम्पादक :** राजेश सिंह